



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 827]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 2010/वैशाख 10, 1932

No. 827]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 2010/VAISAKHA 10, 1932

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2010

का.आ. 992(अ).—माननीय उच्चतम न्यायालय केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य के मध्य सन् 2006 का मूल बाद सं. 3 के मामले में अपने आदेश तारीख 18-2-2010 और तारीख 29-3-2010 द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा माननीय डॉ. ए. एस. आनंद, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति को अध्यक्ष, अध्यक्ष के परामर्श से तमिलनाडु और केरल राज्य द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य से एक सदस्य और अध्यक्ष के परामर्श के केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो तकनीकी सदस्यों को, जो विवाद से संबंधित न हों, से मिलकर बनने वाली सशक्त समिति का गठन करने के लिए निदेशित किया था :

अतः, अब, उच्चतम न्यायालय के उक्त निदेशों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार सशक्त समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- (i) न्यायमूर्ति डॉ. ए. एस. आनंद, —अध्यक्ष  
भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति
- (ii) न्यायमूर्ति श्री के. टी. थॉमस, —सदस्य  
उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश  
(केरल सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट)
- (iii) न्यायमूर्ति डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, —सदस्य  
उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश  
(तमिलनाडु सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट)

(iv) डॉ. सी. डी. थले, —सदस्य

भूतपूर्व सचिव, केन्द्रीय

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार

(केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट)

तकनीकी विशेषज्ञ)

(v) श्री डी. के. मेहता, —सदस्य

भूतपूर्व मुख्य अभियंता केन्द्रीय जल आयोग

(केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तकनीकी विशेषज्ञ)

(vi) श्री सत पाल, —सदस्य सचिव

संयुक्त सचिव

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार

2. सशक्त समिति के अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव को संदेय पारिश्रमिक और अन्य भत्ते, उनके निबन्धन और शर्तें तथा सम्बंधित अन्य मुद्दे अलग से जारी किये जायेंगे।

3. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली होगा।

4. सशक्त समिति, उसके समक्ष वाद के पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी विवादों पर, बिना उन विवादों तक सीमित किए हुए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाए गए थे, सुनवाई करेगी और अपने गठन से छः मास के भीतर यथा संभव शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. समिति बैठक के स्थान के साथ-साथ सुनवाई के लिए अपनी प्रक्रिया विरचित करेगी और समुचित निदेश जारी करेगी।

6. केरल सिचाई और जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 की विधिमन्यता समेत विधिक और संवैधानिक विवादक उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 18 फरवरी, 2010 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचारित किए जाएंगे।

[सं. 11/2/2010-बी.एम.]

यू. एन. पंजियार, सचिव

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2010

S.O. 992(E).—Whereas in the matter of Original Suit No. 3 of 2006 between State of Tamil Nadu Vs. State of Kerala, the Hon'ble Supreme Court *vide* its Orders dated 18-2-2010 and 29-3-2010 directed the Central Government of set up by notification in the Official Gazette, an Empowered Committee comprising of Hon'ble Dr. A. S. Anand, Former Chief Justice of India as the Chairman, One member each to be nominated by the State of Tamil Nadu and Kerala in consultation with the Chairman and two technical experts not connected with the dispute to be nominated by the Central Government in consultation with the Chairman;

Now, therefore, for implementing the said directions of the Supreme Court, the Central Government hereby constitutes the empowered Committee comprising of the following :—

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| (i) Justice Dr. A. S. Anand,         | —Chairman |
| Former Chief Justice of India        |           |
| (ii) Justice Sh. K. T. Thomas,       | —Member   |
| Former Judge of Supreme Court,       |           |
| (Nominated by Kerala Government)     |           |
| (iii) Justice Dr. A. R. Lakshmanan,  | —Member   |
| Former Judge of Supreme Court,       |           |
| (Nominated by Tamil Nadu Government) |           |
| (iv) Dr. C. D. Thatte,               | —Member   |
| Former Secretary, Union Ministry of  |           |
| Water Resources,                     |           |
| (Technical Expert nominated by       |           |
| Central Government)                  |           |

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| (v) Sh. D. K. Mehta,           | —Member |
| Former Chief Engineer, Central |         |
| Water Commission               |         |
| (Technical Expert nominated    |         |
| by Central Government)         |         |

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| (vi) Sh. Sat Pal,       | —Member |
| Joint Secretary,        |         |
| Union Ministry of Water |         |
| Resources               |         |

2. Remuneration and other allowances payable to and terms and conditions thereof as also the matters connected therewith of Chairman, Members and Member-Secretary of the Empowered Committee, shall be issued separately.

3. The Headquarter of the Committee shall be at New Delhi.

4. The empowered committee shall hear to the parties to the suit on all issues that will be raised before them without being limited to issues that have been raised before Hon'ble Supreme Court and furnish a report, as far as possible, within six months from their constitution.

5. The Committee shall frame its own procedure and issue appropriate directions as to the hearing as well as venue of its sittings.

6. The legal and constitutional issues including the validity of the Kerala Irrigation and Water Conservation (Amendment) Act, 2006 would be considered by the Hon'ble Supreme Court as per Supreme Court Order dated 18th February, 2010.

[F. No. 11/2/2010-BM]

U. N. PANJIAR, Secy.